[श्री रामधन]

किरायों में वृद्धि कर रहे हैं तो यह एक बिलकुल ग़लत चीज़ है। जैसे पिछले साल माननीय नंदा जी ने अपनी बजट स्पीच में रेलों के किराये बढ़ाने का प्रस्ताव किया था लेकिन बाद में अपने वृद्धि वाले प्रस्ताव को वापिस ले लिया था वैसे ही वर्त्तमान रेल मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वह जो उन के दिल में जनता के लिए एक हमदर्दी की भावना है और जनता की कराह से जो वह परिचित हैं तो यह जो उन्होंने किरायों में बड़ोत्तरी का प्रस्ताव किया है उस को उन्हें तुरन्त वापिस ले लेना चाहिए। बंगलौर में हमारे वर्तमान रेल मंत्री ने बड़े गर्व के साथ भाषण किया था और उन्होंने कहा था कि संसद सदस्य रेलवे के प्रशासन में रोक टोक करते हैं, इंटरफिअरेंस करते हैं, दखल देते हैं। लेकिन यह दखल क्यों होता है ? इस पर उन्होंने विचार नहीं किया। यह दखल इस लिये नहीं होता है कि किसी को दखल देने का शोक है। वह इस लिये होता है कि रेलवे बोर्ड के जो आदेश होते हैं उन का आप की रेलों में काम करने वाले अधिकारी पालन नहीं करते, बल्कि खुल्लमखुल्ला उन की अवहेलना करते हैं। जो कर्मचारी लोग हैं या दूसरे लोग हैं, आखिर वह किस के पास अपनी गुहार ले कर जाये, अगर संसद् सदस्यों से अपनी बात न कहें ? जो संसद् सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, अगर वह उन की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो क्या यह उन का गुनाह है ? आप कहते हैं कि वह दखलन्द जी करते हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं रेल मंत्री महोदय को। रेलवे बोर्ड का एक सर्कूलर है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के एम्प्लायीज को उन के घरों के नजदीक पोस्ट किया जाये अगर वह कहीं दूर पर हों। अगर वह अपना स्थानान्तरण चाहते हों तो भी उन को घरों के नजदीक पोस्ट किया जाये लेकिन मैं जानता हूं कि सन् 1964 से रेलवे कर्मचारी कोशिश कर रहें हैं अपने घरों के नजदीक जाने की। वह अपनी दस-दस साल की वरियता को भी भूल जाते हैं, अपने खर्च से जाना चाहते हैं, लेकिन उन की बाते नहीं सुनी जाती है। फिर कहा जाता है कि ससंद्-सदस्य हस्तक्षेप करते हैं। आप खुद जो नियम बनाते हैं, रेलवे बोर्ड जो नियम बनाता है, उन का पालन आप के द्वारा नहीं किया जाता। जब भी आप का ध्यान इस तरफ खींचा जाता है तब आप कहते हैं कि प्रशासन में हस्तक्षेप हो रहा है।

17.32 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FIRST REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SANSADIYA KARYA TATHA NAUWAHAN AUR PARIWAHAN MANTRI) (SHRI RAJ BAHADUR) : I beg to present the First Report of the Business Advisory Committee.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION *Re.* REPORT OF COMMISSION ON CAR PRICES

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : The automobile industry in the country is one of the most pampered monopolies. It has ruthlessly exploited the sellers' market prevailing in the country. With almost impunity, it has turned a deaf year to the consumers' needs as well as its obligations to society I sometimes wonder if there is a conspiracy hatched between the Government of India and the automobile manufacturers. In the last decade, the price of passenger cars have incerased by 100 per